International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 05-06-2022, Accepted: 22-06-2022, Published: 07-07-2022
Volume 4, Issue 2, 2022, Page No. 1-4

इजराइल–फिलिस्तीन विवाद के सम्बन्ध में भारत की भूमिका

प्रीतिशा गौतम[1], अनुपमा सिंह[2]

[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] पर्यवेक्षिका, राजनीति विज्ञान विभाग, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

वैश्विक परिदृश्य में संघर्ष का इतिहास अत्यन्त पुराना है जहाँ एक ओर बदलती विश्व व्यवस्था अपनी सामरिक और भू–राजनीतिक शक्तियों को लेकर संघर्ष के मार्ग का चयन करता आ रहा है। यही कारण है कि सामरिक (रणनीतिक) व्यवस्थाओं का काल प्रर्यन्त अपने स्वरूप और आयामों को बदलती रही इसमें कभी सामरिक बढ़त के लिये संघर्ष किया गया तो कभी धार्मिक, नस्लीय उन्माद जैसे–उत्प्रेरक बलों की संवेदना से प्रभावित मानव के संघर्ष मार्ग को अनवरत जारी रखा था। जिससे यह संघर्ष की भूमिका तैयार हो गयी और दिन प्रतिदिन संघर्ष को एक नया स्वरूप मिलता गया भारत के साथ ही साथ अन्य देश जैसे अमेरिका इस समस्या को देखते हुए अमेरिका के द्वारा मध्य पूर्व देश के लिये शांति योजना की घोषणा की गई थी। अमेरिका द्वारा घोषित इस शांति योजना का मुख्य उद्देश्य इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों जैसे–इजराइल की सीमा, फिलिस्तीन शरणार्थियों की स्थिति, सुरक्षा सम्बन्धी, चिंतायें और येरूशलम आदि को सम्बोधित कर भू–क्षेत्र विशेष में शांति स्थापित करना है। जहाँ एक ओर इजरायल के प्रधानमंत्री ने यथार्थवादी मार्ग बताया है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसे राष्ट्रीय हित करार देते हुये इसका विरोध जताया है विरोध के दौरान ओस्लों समझौते के अनुसार मध्य–पूर्व शांति प्रक्रिया की गयी और एक समय तालिका बनी थी जिसके अनुसार पश्चिमी देशों में स्थित गाजा और जेरिको में फिलिस्तीन की एक अंतरिम सरकार होगी, आगे चलकर ओस्लो समझौता सन् 1990 में हुआ इसका औपचारिक रूप से गाजा पर इसराइली–फिलिस्तीन अंतरिम समझौता की बात की गयी फिलिस्तीन ने इसका विरोध किया और कहा कि येरूशलम के विषय में इस समझौते पर कोई चर्चा अथवा निर्णय नहीं लिया गया है, इस वजह से फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमुद अब्बास ने इसको मान्यता ना देते हुये इस समझौते से अपने को अलग किया था।

मूल शब्दः इजराइल–फिलिस्तीन विवाद, भारत की भूमिका

प्रस्तावना

भारत और इजराइल के सम्बन्ध की बात करें तो भारत ने 29 जनवरी सन् 1992 को भारत ने इजराइल को मान्यता के तौर पर स्थापित किया तथा साथ ही साथ पारस्परिक रूप से पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोनों देशों ने आपसी भागीदारी की 28वीं वर्षगांठ के पड़ाव को दोनों देशों ने पार किया है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध आर्थिक, सैन्य, कृषि एवं राजनीतिक स्तरों पर पल्लवित एवं पुष्पित हुआ है। भारत और इजराइल दोनों ही अपने पड़ोसी देशों से आतंकित एवं त्रस्त प्रतीत होते हैं और दोनों देश अपने पारस्परिक सम्बन्धों को रणनीतिक सम्बन्ध के तौर पर देखते हैं। भारत ने 1950 में इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और इजराइल को यह अनुमति दी गयी कि वह भारतीय दूतावास खोल लें ताकि भारतीय यहूदी नागरिकों को इजराइल जाने व इजराइल नागरिकों को भारत आने की अनुमति मिल सके। इजराइल हमेशा से भारत की मदद के लिये तैयार रहता था जब कभी भी राष्ट्रीय समस्या आयी है तो इजराइल ने हमेशा से भारत का साथ दिया है चाहे वह वर्तमान के दौर की बात हो या अतीत के दौर की बात हो हमेशा से सहयोग किया है। सन् 1962 के भारत–चीन के मध्य युद्ध हो या फिर सन् 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो या फिर सन् 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो साथ ही 1999 में भी कारगिल संघर्ष में भी इजराइल का योगदान अविस्मरणीय है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय देशों का दबाव भी इजराइल पर था लेकिन इजराइल ने हमेशा से भारत का साथ दिया है। दोनों देशों के बीच समानतायें भी है और इसीलिये भारत में इजराइल के राजदूत एलोन उशविज ने भी दोनों देशों के रिश्तों की समीक्षा की और इन्हें ऐसे विश्वसनीय मित्र के रूप में देखा जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और साथ ही एक चुनौतियों का सामना करते हैं।

नियति एवं अतीत की घटनाओं के चक्र ने भी भारत और इजराइल को स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आने के लिये प्रेरित किया। भारत और इजराइल के बीच साझेदारी धीरे–धीरे विकसित होती जा रही है और इन दोनों देशों ने विविध क्षेत्रों–जैसे उच्च तकनीकी युक्त उत्पाद, रक्षा परिसज्जा, सुरक्षा, कृषि, जल प्रबन्धन संसाधन, औषधि निर्माण एवं सूचना तकनीक में पारस्परिक भागीदारी विकसित भी है। इन दोनों देशों के बीच सम्बन्ध निःसन्देह विस्तार की तरफ अग्रसर रहे जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी और इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में संभव हो सका श्री नरेन्द्र मोदी और नेतन्याहू के बीच मित्रता कई चर्चित विषयों में से एक है जो हमेशा राष्ट्रीय हित एवं अपने को साझा करते हुये अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बनी रहती है हालांकि भारत और इजराइल एक दूसरे के सहयोगी और सहभागी कई दशकों से रहे हैं, लेकिन इनके बीच मित्रता का भाव सबसे अधिक भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इजराइली प्रधानमंत्री श्री

नेतन्याहू के शासन काल में ही दिखायी देती है। ये दोनों देश भगौलिक रूप से काफी दूर रहे हैं परन्तु मानसिक सन्निकटता सबसे अधिक है। भारत ने जो भाव इजराइल के समक्ष रखा वही भाव व मित्रता फिलिस्तीन के प्रति भी सदैव रही है इसका मुख्यतः यही कारण रहा है कि वह यथार्थवादी नीति के मार्ग को अपनाता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जो सम्बन्ध इजराइल के प्रति दर्शाता है वही सम्बन्ध फिलिस्तीन के साथ संतुलित सम्बन्धों की शुरूआत भी है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों से समानांतर स्तर पर रिश्ते प्रगाढ़ करने के लिये सक्रिय है। इसके अलावा, फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि वो किसी से भी रिश्ते बना सकता है। हालांकि भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन करना जारी रखा और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मुहम्मद अब्बास के नेतृत्व को भारत सरकार ने भी अपना वैचारिक समर्थन प्रदान किया।

अप्रैल, सन् 2015 को फिलिस्तीन के मुद्दे पर एशियन अफ्रीकन कोम्मेमोरिटिव कांफ्रेस में भी भारत के द्वारा समर्थन जारी रखा गया इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के परिसर में फिलिस्तीन झंडे का भी अनुमोदन किया गया साथ ही 128 देशों में भारत भी एक देश रहा जिसने दिसम्बर, 2017 को झंडा प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन दिया और येरूशलम को इजरायल की राजधानी बनाये जाने का वैचारिक समर्थन किया। इस तरह अमेरिका येरूशलम से तेल अवीब स्थानांतरित कर दिया गया था जो की भारत और फिलिस्तीन के बीच कई बार उच्च स्तरीय राजकीय यात्राओं का दौरा किया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा भी की जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा थी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी को फिलिस्तीन के सर्वोच्च नागरिक सुझाव से नवाजा गया क्योंकि फिलिस्तीन की समस्या को भारत के द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है।

भारत और इजरायल

भारत–इजरायल के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों को बीत करे तो यह सन् 1992 तक भारत तथा इजरायल के मध्य किसी प्रकार के सम्बन्ध नहीं रहें। इसके मुख्यतः दो कारण थे– पहला, भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था जो कि पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था और दूसरा गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की तरह इजराइल को मान्यता नहीं देता था। दूसरा मुख्य कारण फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थक रहा है यहाँ तक कि 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन नामक संगठन का निर्माण किया परन्तु 1989 में कश्मीर में विवाद तथा सोवियत संघ के पतन तथा पाकिस्तान के गैर कानूनी घुसपैठ के चलते राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन आया और भारत ने अपनी सोच बदलते हुये इजराइल के साथ सम्बन्धों को मजबूत करने पर जोर दिया तथा 1992 से नया दौर आरम्भ हुआ। भारत–इजराइल सम्बन्ध आज काफी परिपक्व एवं मधुर है दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्ध समय के साथ अधिक स्थिर एवं मजबूत हो रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति फिलिस्तीन के साथ भारत के ऐतिहासिक सम्बन्ध, भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन से धार्मिक और सामाजिक लगाव आदि वे मूल कारण थे। इजराइल और स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत का उदय एक ही वर्ष 1947 ई0 में हुआ है। हालांकि अधिकारिक तौर पर इजराइल को स्वतः 1948 में मिली देशों के शुरूआती सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। 1947 में ही भारत ने इजराइल को एक शब्द के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया। इसी तरह से 1949 में एक बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को सदस्य देश बनाने के विरोध में वोट किया शुरूआती दो वर्षों के खराब रिश्तों के बावजूद 1950 में भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। नेहरू युगीन विदेश नीति जिसमें तीसरी दुनिया की एकता और अहिंसा के सिद्धान्त अहम हैं और साथ ही भारत फिलिस्तीन का भी खुलकर समर्थन करता आ रहा है।

इजराइल–फिलिपींस संघर्ष का इतिहास

इजराइल ने पश्चिम देशों के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया था जिसके फलस्वरूप जार्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया इस पूर्वी हिस्सों को बाद में इजराइल ने स्वतः इसको अधिकृत कर लिया इसके साथ ही इजराइल मध्य पूर्वी जार्डन, येरूशलम पर अपना अधिकार स्थापित किया है। फिलिस्तीन पूर्वी येरूशलम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे परन्तु इजराइल मध्य पूर्वी भाग को अपनी ''एकीकृत, शाश्वत राजधानी के रूप में देखता है। परन्तु फिलिस्तीन इस सम्बन्ध के नेतृत्व में किसी भी समझौते से इन्कार करता है क्योंकि वह पूर्वी यरूशलम प्रकार के को अपनी राजधानी मानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष को देखा जाये तो वह लगभग 100 साल पुराना है जिसकी शुरूआत वर्ष 1917 में उस समय हुयी जब तत्कालीन ब्रिटिश सचिव आर्थर जेम्स बल्फौर हित के निर्माण के लिये ब्रिटेन का अधिकारिक समर्थन व्यक्त किया था। इस समर्थन के बावजूद अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब तथा यहूदियों के दावे का समाधान करने के लिए इस मुद्दे को नव निर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र ;न्छद्ध के विचारार्थ प्रस्तुत किया।

वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी साथ ही इजराइल एक देश बन गया। इसमें परिणामस्वरूप विभिन्न देशों ने अरब राज्यों जैसे इजिप्ट, जार्डन, इराक, सीरिया आदि ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया और जब इनके बीच हुये युद्ध की समाप्ति हुयी तो इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से अधिक भूमि को अधिकृत कर उस पर अपना अधिकार प्रतिस्थापित कर लिया इसके पश्चात् दोनों देशों के मध्य संघर्ष तेज होने लगा और वर्ष 1967 में प्रसिद्ध सिक्स डे वार हुआ पूर्वी येरूशलम को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। वर्ष 1987 में अपनी अधिकृत भूमि के स्वरूप फिलिस्तीन में 'हमास' नामक आतंकवादी हिंसक संगठन का गठन किया गया इसका गठन हिंसक जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के प्रत्येक भाग पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया था। समयानुसार वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के अधिकृत क्षेत्रों में तनाव व्याप्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1987 में प्रथम फिलिस्तीन विद्रोह हुआ जो कि फिलिस्तीन सैनिकों और इजराइली सेना के मध्य एक छोटे युद्ध में परिवर्तित हो गया जो दोनों देशों के मध्य संघर्ष का कारण बना है।''

इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का मुद्दा

वेस्ट बैंक

इजराइल फिलिस्तीन हमेशा से क्षेत्रों को लेकर संघर्ष को अनवरत रहता है। इजराइल में अधिकांश मध्य पूर्वी भाग पर अपना अधिकार किया है तथा मध्य पूर्व के देश वेस्ट बैंक इजराइल और जार्डन के मध्य में स्थित है। वेस्ट बैंक का सबसे बड़ा शहर 'रामल्लाह' है जो फिलिस्तीन की वास्तविक राजधानी मानी जाती है। परन्तु इजराइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमुद अब्बास के विरूद्ध था। इजराइल के इस बर्ताव के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी और ये क्षेत्र पूर्णतः नहीं अपितु अधिकांश भाग उसके हिस्से में जा चुका है जो संघर्ष का मुख्य मुद्दा है जिसकी माँग फिलिस्तीन करता आ रहा है वह इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता है।

गाजा पट्टी

गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के मध्य स्थित है। ये वह क्षेत्र है जो इजराइल के द्वारा वर्ष 1967 में अधिग्रहण किया गया था, किन्तु गाजा शहर के लगभग पूर्ण क्षेत्रों के नियंत्रण तथा उसके शासन को नियंत्रण करने के लिये 1990 में ओस्लो समझौतों के द्वारा किया गया परन्तु ओस्लो समझौते में फिलिस्तीन की हित की बात न होने के कारण फिलिस्तीन सत्ता के अधीन इसको स्वीकार नहीं किया था। इजराइल इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का पूर्णतः प्रयास करता रहता है उसने इस कार्य को आगे बढ़ाते हुये वर्ष 2005 में इजराइल ने इस क्षेत्र से यहूदी नागरिकों की बस्तियों को हटा दिया इजराइल हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इन पर पहुँच से नियंत्रण बनाये रखा है।

गोलन हाइट्स

इजराइल उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभिन्न शहर जार्डन सीरिया, लेबनान, मिस्र से घिरा हुआ है। इजराइल ने गोलन हाइट्स एक सामरिक पठार है जिसे इजराइल ने वर्ष 1967 में सीरिया से युद्ध करके छीन लिया था इतना ही नहीं वह वर्ष 1981 में इस क्षेत्र पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया है परन्तु उसके इस स्तर के बदलाव को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान नहीं की गई थी।

हमास

हमास को अमेरिकी सरकार द्वारा गठित एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है चूँकि ये हमास इजराइल की देख–रेख में कार्य करता है हमास वह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठन है जो हमेशा सक्रिय रूप से इजराइल का साथ देता आ रहा है। हमास के द्वारा वर्ष 2006 के फिलिस्तीन प्रधिकरण के विधायी चुनावों में अपनी जीत दर्ज की थी उसने फिलिस्तीन में अधिकांश भागों को जीता है तथा इसकी देखरेख इजराइल के नेतृत्व में किया गया है। इजराइल मध्य पूर्व के भागों को अधिकृत करने में हमास का हाथ प्रत्यक्ष ना सही परन्तु परोक्ष रूप से पाया गया है। सन् 2007 में गाजा पर भी हमास द्वारा अधिकार कर उसको भौगोलिक रूप से विभाजित कर दिया।

जेरूशलम

जेरूशलम को लेकर दोनों ने दावा किया वह जेरूशलम को राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं जेरूशलम एक धार्मिक पवित्र स्थल और सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र माना जाता है इस क्षेत्र को लेकर दोनों में विवाद सा उत्पन्न है परन्तु इसका निर्णय करना कठिन है।

इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष और भारत

भारत ने स्वतंत्रता के पूर्व से लेकर पश्चात् तक लम्बे समय से इजराइल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं रखे थे, जिससे यह स्पष्ट था कि भारत फिलिस्तीन की माँगों का समर्थन करता है, किन्तु वर्ष 1992 में इजराइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध बने और अब ये रणनीतिक (सामरिक) सम्बन्ध में परिवर्तित हो गये हैं तथा आज की वर्तमान स्थिति में भारत–इजराइल का सम्बन्ध काफी गहरा है।

भारत–फिलिस्तीन सम्बन्ध प्रारम्भ से ही काफी घनिष्ठ रहे थे तथा भारत–फिलिस्तीन की समस्याओं के प्रति काफी संवेदनशील रहा है। फिलिस्तीन मुद्दे के साथ भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीन के साथ मित्रता बनी रही है। भारत–फिलिस्तीन सम्बन्ध भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग रह है। वर्ष 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरूद्ध मतदान किया था अथवा भारत कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है।

भारत पहला गैर–अरब देश था, जिसने वर्ष 1974 में फिलिस्तीन जनता के एक मात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी थी। भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले शुरूआती देशों में शामिल था। भारत ने फिलिस्तीन से सम्बन्धित कई प्रस्तावों का समर्थन किया है, जिनमें सितम्बर 2015 में सदस्य राज्यों के ध्वज की तरह अन्य प्रेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीन ध्वज लगाने का भारत का समर्थन प्रमुख है। फिलिस्तीन का समर्थन करने के अलावा भारत ने इजराइल का भी काफी समर्थन किया है और दोनों देशों के साथ अपनी संतुलन नीति को बनाये रखा है। भारत का मानना है कि इस क्षेत्र में स्थिरता लाने और इनके संघर्ष को जो दशकों पुराना है इसको समाप्त करने के लिये शांति वार्ता ही एक मात्र उपाय अथवा समाधान है। भारत–इजराइल सम्बन्ध 1950 से बनते आ रहे हैं वह एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तथा एक दूसरे का साथ व सहयोग करते आ रहे हैं इसी के विपरीत फिलिस्तीन भी कहीं ना कहीं भारत पर पूर्ण विश्वास को बनाये हुये हैं फिलिस्तीन यह चाहता है कि भारत वार्ताकार के रूप में कार्य करे क्योंकि उसका विश्वास अमेरिका, रूस, चीन पर ज्यादा नहीं है क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना येरूशलम को अपनाना चाहता है।

आगे की राह

दोनों राज्यों की राजनीति में नेतृत्व और पीढ़ीगत परिवर्तन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।
इजराइल और फिलिस्तीन दोनों प्रधानमंत्री काफी लम्बे समय से सत्ता में है क्योंकि सत्ता के लिये घरेलू अस्तित्व की राजनीति और अपने पद पर बने रहने की इच्छा इस क्षेत्र और उसके व्यापक हित पर हावी है। नई सत्ता के आने से ही राज्य के समाधान हेतु पुनर्विचार की उम्मीद है। फिलिस्तीनी हमास संगठन को भी नियंत्रण में लाने की आवश्कता है।
दोनों राज्यों की एक निश्चित सीमा होनी चाहिये जिस तक वे अपनी कारवाही कर सके तथा बल का अनुपातहीन उपयोग कोई समाधान नहीं है, यह केवल आतंकवाद और उग्रवाद पैदा करेगा। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय देशों के पास संभवतः अमेरिका की तुलना में शांति वार्ता हेतु बेहतर भाग उपलब्ध है। अमेरिका का पहले इस पर पूर्ण नियंत्रण था तथा आज की स्थिति में वह इस पर नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है। कतर और मिस्र पहले से ही शांति हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं।

निष्कर्ष

इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष काफी भयानक होता जा रहा है तथा स्थिति आज धरातल पर खराब होती जा रही है समय के साथ ही साथ संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इजराइल लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका है फिलिस्तीन के आधे से अधिक क्षेत्रों पर अपनें आतंकवादी सगंठन के सहारें अधिकार कर चुका है। भारत नें इस संघर्ष को समाप्त करने के लिये शांतिवार्ता की माँग की और कहा संघर्ष कों जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है परंतु फिलिस्तीन अपनें लिये एक स्थायी भूमि की माँग कर रहा है तथा कहने का तात्पर्य यह है की वह येरूशलम यह चाहता है तथा इजराइल येरूशलम गाजा, वेस्ट बैंक पर भी अपना अधिकार किया है। शांति वार्ता के लियें भारत का रूख अभी–भी कायम है जो भविष्य में सम्भव नही है। दोनों पक्षों को एक संभावित समाधान पर पहुँचाना होगा जों आपसी हित में हो लेकिन यह केवल वार्तालाप से ही हो सकता है ना की युद्ध के माध्यम सें शांतिपूर्ण समाधान के लिये वैश्विक स्तर पर देशों को इस मुद्दे पर एक होकर इस जटिल विषय पर वार्ता सम्मेलन की आवश्यकता है, तथा सभी हितधारक देश एक साथ उपस्थित होकर इस समस्या का समाधान खोजनें का प्रयास करें। इजराइल और फिलिस्तीन के बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बयान जारी किया है की सभी हिंसक गतिविधियों खासकर गाजा से किये गये रॉकेट हमलों की निन्दा की है साथ ही हिंसा पर रोक लगाने की जरूरत पर जोर दिया है।

सन्दर्भ सूची

1. पी०आर० कुमार स्वामी, इंडिया इजराइल पॉलिसी, पब्लिकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी 2010 ISBN No. (10) 0231152043
2. यू०आर०घई अन्तंराष्ट्रीय राजनीति (सिहात तथा व्यवहार), न्यू एकेडमिक पब्लिकेशन कंपनी।
3. ब्रज कुमार पाण्डेय, भारत–इजराइल सम्बन्ध, अभिधा प्रकाशन, प्रथम संस्करणk ISBN No. (13) 978-93-80859-81-1
4. हर्ष वर्धन पंत, भारतीय सुरक्षा एवं विदेश नीति, प्रकाश पब्लिकेशन 2012, ISBN No. (10) 9350481413
5. वेवटर्न मिल्टन एडवर्ड्स, द इसराइली– फिलिस्तीन कन्फलिक्ट आ पीपुल वॉर रूटलेज 2008, ISBN No. (10) 041541044
6. पेलेग एंड वैक्समन, इजराइल फिलिस्तीनीः द कन्फलिक्ट वीधिन, पब्लिकेशन कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रेस 2011, ISBN No. (10) 0521157021
7. जे0 एन0 दीक्षित, भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली संस्करण 2007
8. वी0 पी0 दत्त, बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, प्रथम संस्करण, 2003, नई दिल्ली
9. (डॉ0) दीनानाथ वर्मा, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, ISBN-8171390595
10. वर्ल्डफोकस भारत की विदेश नीतिः भाग 2 ISBN No. 2231-0185.
11. https://dhyeyaias.com
12. www.aajtak.in
13. https://www.amarujala.com
14. newspaper.thehindu
15. संकेताक्षर (मुख्य शब्द) –मध्यपूर्व स्थिति, शांति, आंतरिक सहयोग, सीमा विवाद, भारत की शांति वार्ता, संधि समझौता हेतु सहयोग, येरूशलम मुद्दा।